

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 905 / 2013 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट प्रथम—झूंगरपुर, वृत—झूंगरपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी,  
अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओड़ा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.कुमार,  
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12 / 09 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी—विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 81 / 11 / आरवेट / 2009–10 / एल / 10–11 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम—झूंगरपुर, वृत—झूंगरपुर. (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति 66,749 /— को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.03.2009 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या जीजे-6 टीटी-420 को जागड़िया (गुजरात) से भीलवाड़ा जाते समय रुकवा कर चैक किया गया। वक्त जांच के दौरान वाहन चालक/माल प्रभारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों में मैसर्स इंडिया रोड एयर लाइन्स का जी.आर.संख्या 2905 दिनांक 03.03.2009 एवं मैसर्स राम एल्कली एण्ड कैमिकल्स का इन्वाइस नं. 19122 दिनांक 03.03.2009 पेश किया। वैट-47 साथ में नहीं पाये जाने के सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष जवाब पेश किया गया। चूंकि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा आयातित माल नियम 53 के तहत अधिसूचित माल था, जिसके लिये परिवहन पर वैट 47 होना आवश्यक था। परन्तु वक्त जांच वैट 47 नहीं पाया गया। माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करके सक्षम अधिकारी ने शास्ति राशि 66,749 /— रूपये आरोपित कर दी। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.12.2010 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वक्त वाहन चैकिंग विवादित माल जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर, नियम 2005 के नियम 53 के तहत राज्य में आयात करने पर अधिसूचित माल है जिसके परिवहन पर घोषणा पत्र वेट 47 अनिवार्य था परन्तु वक्त जांच वैट घोषणा पत्र नहीं पाया गया। सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपण पारित किया है वह धारा 76 व नियम 53 तथा नियम 56 एवं 57 के अनुरूप विधिनुकूल आदेश था जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरुद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने उक्त प्रकरण मैसर्स डी.पी. मेटल्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप भूलवश ट्रांसपोर्टरों के यहां रह गये छूट गये घोषणा पत्र को जांच तिथि के अगले ही दिन प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के शास्ति आदेश को निरस्त किया जाना विधिनुकूल है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने (2016) 14 RGSTR 130 (RHC) स.वा.क.अ., भरतपुर बनाम मै.0 हिन्दुस्तान कोका-कोला बेवेजस प्रा.लि. निर्णय दिनांक 01.06.2016, (2016) 14 RGSTR 57 (RHC) स.वा.क.अ., भरतपुर बनाम मै. बंशीधर रामस्वरूप, निर्णय दिनांक 01.06.2016, मै.0 हीरामणी फूड प्रोडेक्ट्स, किशनगढ़, बनाम स.वा.क.अ. बांसवाड़ा व अन्य आदि के दृष्टान्त प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। सम्बन्धित माल के आयात/परिवहनित करने पर वक्त जांच चैकिंग के समय अधिनियम की धारा 76(2), 79 सपष्टित नियम 53 के प्रावधान अनुसार वेट 47 प्रपत्र मार्गस्त माल के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना विधिक अनिवार्यता है, परन्तु वक्त जांच उक्त अपेक्षित घोषणा पत्र वैट 47 नहीं पाया गया। ऐसे प्रकरणों में डी.पी. मेटल्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो उसका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दृष्टान्त एसीटीओ, एफएस भरतपुर बनाम हरसहाय द्वाराका प्रसाद अग्रवाल वो. 43 पार्ट 7 टैक्स अपडेट पृष्ठ 230 में निम्न प्रकार उल्लेखित किया है :—

*"In my view, the order of the Tax Board deserves to be upheld for the reason that the declaration form, which was obtained by the assessee, was available with them, and which was produced immediately on demand, and even on the same day of intercepting the vehicle. Admittedly, it is not a cast that the declaration form was obtained subsequent to the dispatch of the goods or after being intercepted by the authorized officer of the Revenue, and admittedly the vehicle was checked on June 23, 1999 on an information going by the vehicle incharge to the assessee, he appeared before the authorized officer himself on the same day, i.e. June 23, 1999 and produced decalration form ST-18C, therefore, once it is a finding of fact given by the assessing officer that the declaration form was produced on the same day on June 23, 1999 when the vehicle was intercepted, in my view, in the light of the judgment rendered by the honourable apex court in the case of D.P. Metals [2001] 124 STC 611 (SC)' [2002] 1 SCC 279 and in the light of the rule 54 of the RST Rules, which postulate that principle of natural justice demand that an opportunity should be given and therefore, it is a clear cut case where the declaration form, though mandatory, required to be carried with the vehicle but the driver/vehicle incharge forgot to carry the same, which was immediately produced on demand that too on same day."*

-: 3 :-

अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. उपरोक्त विश्लेष्ण के आलोक में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

।  
।  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य